



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 223]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2015

सं. 30/2015-20

विषय: विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 और 3.08 में संशोधन।

फा. सं. 01/61/180/33/एम 16/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त षवित्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 3.06 और 3.08 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. पैरा 3.06 में संशोधन :

नए उप-पैराग्राफ (ख) और (ग) को शामिल किया जा रहा है तथा संशोधित पैराग्राफ 3.06 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

3.06 क्षेत्राधिकारी आर ए/संबंधित आर ए

(क) आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के तहत आवेदन-पत्र/आवेदन-पत्रों को सौंपने के लिए आईसी पर पृष्ठांकित कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय के पते के आधार पर क्षेत्राधिकारी आर ए को चुनने का विकल्प रहेगा। इस विकल्प का वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चयन करना होगा। यदि एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है तो उस वर्ष से संबंधित दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक आवेदक ने 2015-16 के दौरान किए गए निर्यात के लिए प्रतिफल का दावा करने हेतु आर ए चेन्ई का चुनाव किया है तो 2015-16 के लिए किए गए निर्यात के लिए सभी दावे, आवेदन-पत्र की तिथि को ध्यान में रखे बगैर, केवल आर ए चेन्ई को ही किए जाएंगे।

(ख) आयातक-निर्यातक कोड (आईसी) धारक जिनकी एसईजेड/ईओयू में इकाईयां हैं, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में उपलब्ध भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा के निर्यात संबंधी स्कीम (एसईआईएस) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट 1क में उल्लिखित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंधित विकास आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

- (ग) यदि आईसीसी धारकों की इकाईयां एसईजेड/ईओयू तथा डीटीए में स्थित हैं तो ऐसे आईसीसी धारक विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में उपलब्ध एमईआईएस तथ एसईआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन निम्नानुसार करेंगे:-
- डीटीए यूनिटों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए), विदेश व्यापार महानिदेशालय को आवेदन किया जाना चाहिए, जैसा कि परिशिष्ट 1 क में दिया गया है ;
 - एसईजेड/ईओयू यूनिटों द्वारा संबंधित विकास आयुक्त (डीसी), एसईजेड को आवेदन किया जाना चाहिए, जैसा कि परिशिष्ट 1क में दिया गया है ।

2. पैरा 3.08 में संशोधन:-

पैरा 3.08 (क) के तहत एक नया उप-पैरा (iv) शामिल किया जा रहा है और संशोधित पैरा 3.08 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

3.08 स्क्रिप के पंजीकरण का पत्तन:-

(क) एमईआईएस के तहत पंजीकरण का पत्तन निम्नानुसार होगा:-

- एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (अलग-अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा।
 - ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को निर्यात के पत्तन पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग को अनुमत करने से पहले किया जाना है। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत होने के बाद, आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत मैनुअल पत्तन पर स्क्रिप को स्वतः ही प्रयोग किया जा सकता है।
 - यदि पंजीकरण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है, किसी अन्य पत्तन पर आयात के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।
 - चूंकि एसईजेड गैर-ईडीआई पत्तन है, अतः स्क्रिप का पंजीकरण एसईजेड पत्तन पर किया जाएगा और यदि स्क्रिपधारक स्क्रिप का उपयोग अन्य पत्तन से आयात हेतु करना चाहता है तो संबंधित विकास आयुक्त टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) जारी करेगा।
- (ख) यदि भारत से सेवा निर्यात स्कीम के तहत स्क्रिप का आवेदन किया गया है, आवेदक किसी भी पंजीकरण के पत्तन का चुनाव कर सकता है और इसका आवेदन-पत्र के उपयुक्त कॉलम में उल्लेख कर सकता है। आरए ऐसे पंजीकरण के पत्तन के साथ स्क्रिप को जारी करेगा। ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को ड्यूटी क्रेडिट के पंजीकरण के पत्तन पर पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक होगा। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत करवाने के बाद, स्क्रिप को स्वतः ही आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन पर और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत किसी मैनुअल पत्तन पर प्रयोग किया जा सकता है। यदि पंजीकरण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है तो किसी अन्य पत्तन पर आयातों के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

एसईजेड और ईओयू में अवस्थित यूनिटों द्वारा एमईआईएस और एसईआईएस के तहत आवेदन की जाने वाली प्रक्रिया को और स्पष्ट किया गया है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th August, 2015

No. 30/2015-20

Subject : Amendment in paragraph 3.06 and 3.08 of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20

F. No. 01/61/180/33/AM 16/PC 3.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes the following amendments in paragraph 3.06 and 3.08 of Handbook of Procedures 2015-2020:

1. Amendment in paragraph 3.06:

New sub-paragraphs (b) & (c) are being inserted and the amended paragraph 3.06 shall read as under:

3.06 Jurisdictional RA / RA Concerned

- (a) Applicant shall have option to choose Jurisdictional RA on the basis of Corporate Office/ Registered Office/Head Office/Branch Office address endorsed on IEC for submitting application/applications under MEIS and SEIS. This option need to be exercised at the beginning of financial year. Once an option is exercised, no change would be allowed for claims relating to that year. To illustrate, if an exporter has chosen RA Chennai for claiming rewards for exports made in 2015-16, then all claims for exports made in 2015-16, irrespective of the date of application shall be made to RA Chennai only.
- (b) **Importer Exporter Code (IEC) holders having units in SEZs /EOUs shall apply to the concerned Development Commissioner of Special Economic Zones (SEZs) given in Appendix 1A for availing benefit under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) and Service Exports from India Scheme (SEIS) provided in FTP 2015-2020.**
- (c) **In case of IEC holders that have units in SEZ/EOUs as well as in DTA, such IEC holders, for availing benefits under MEIS and SEIS provided in FTP 2015-2020, shall file their applications as under :-**
 - (i) **DTA units shall apply to concerned Regional Authority(RA), DGFT as given in Appendix 1A;**
 - (ii) **SEZ/EOU units shall apply to concerned Development Commissioner (DC), SEZ as given in Appendix 1A.**

2. Amendment in paragraph 3.08

Under paragraph 3.08(a), a new sub-paragraph (iv) is being inserted and the amended paragraph 3.08 shall read as under :

3.08 Port of Registration of Scrips

- (a) Port of Registration under MEIS would be as follows:
 - (i) Duty Credit Scrip (including splits) under MEIS shall be issued with a single port of registration which shall be the port of export.
 - (ii) Duty credit scrip needs to be registered at the port of exports. This is to be done prior to allowing usage of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advice (TRA) procedure.
 - (iii) In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.
 - (iv) **SEZs being non-EDI Ports, the scrip shall be registered at the SEZ port and in case the scrip holder intends to use the scrip for import from another port, the concerned DC shall issue Telegraphic Release Advice (TRA).**
- (b) In case of scrip applied under Service Exports from India Scheme, the applicant can choose any port as port of registration and mention it in the application at the appropriate column. RA will issue the scrip with such port of registration. Such Duty credit scrip needs to be registered at the port of registration of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically be used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advice (TRA) procedure. In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.

Effect of this Public Notice :

Procedure for filing applications under MEIS and SEIS by units located in SEZs and EOUs has been further clarified.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade